

Dear Prasar Bharati Employees, OPEN YOUR EYES

भाइयों कभी ध्यान दिया की आप लोग प्रसार भारती के कर्मचारी क्यों हो ?

आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का स्टेटस क्यों नहीं मिला ?

यदि 05/10/2007 की कटऑफ डेट नहीं होती तो आप लोग Govt. Employee होते या नहीं होते ?

???? कौन है इसका जिम्मेदार ????

यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं की उस समय ARTEE व National Federation (NFADE) दोनों कर नेतृत्व श्री अनिलकुमार जी ही कर रहे थे । GOM के साथ मीटिंग भी उन्होंने ही की थी । सारे तथ्य उन्होंने ही GOM के सामने रखे थे । आज वे हर बात के लिये ARTEE को जिम्मेदार ठहराते हैं । जरा सोचिये जब GOM 05/10/2007 की कटऑफ डेट तय कर रहा था अनिल जी और NFADE क्या कर रहा था ? यह हैरानी की बात है की यह फैसला हुआ 05/10/2007 की GOM की मीटिंग में हुआ की *आज तक के सब कर्मचारी Govt और आज के बाद के भर्ती हुए लोग PB के कर्मचारी होंगे । यही फैसला 2009 की GOM की मीटिंग में Approve हुआ । यही माननीय संसद ने PB एक्ट में संशोधन 2012 में किया । 05 Oct 2007 का निर्णय क्या था ?

आज तक के सब कर्मचारी Govt और आज के बाद के भर्ती हुए PB के कर्मचारी होंगे ।

तो 2012 तक के कर्मचारी को Govt. Employees का स्टेटस मिलना चाहिए था या कम से कम 2009 तक वालों को तो दिलवा देते । इनमे से बहुत सारे ARTEE के Life Member हैं । किन्तु एक cutoff date ने एक झटके में आप सब लोगों का भविष्य अंधकारमय कर दिया । आज PB कर्मचारी हताशा में हैं और छोड़कर जा रहे हैं चूँकि 4200 ग्रेड Pay में काम करना पड रहा है ।

जरा सोचिये की अगर ये 05/10/2007 की cut off नहीं होती तो आप लोगो को 4600 grade pay भी मिलता और 7th pay कमीशन भी और अब यह भेदभाव आगे भी चलता रहेगा !! यानी अनिलजी की देन, 25/2/1999 के बाद एक और कटऑफ date, 05/10/2007. We again say that की ये यदि ये दो cutoff dates 25/2/1999 व 05/10/2007 नहीं होती तो आज आप सब सरकारी कर्मचारी होते । आप सब को स्वतः ही 6500-10500 का scale यानि 4600 ग्रेड pay और 7th वेतन आयोग स्वतः ही मिलता ।

We are re producing the excerpts of a report जो साफ़ साफ़ कहती है की Hon'ble GoM ने फैसला लेने से पहले NFADE व ADASA से बात की थी । यह सरकारी दस्तावेज है । कोई भी चाहे इसकी जांच कर सकता है ।

e Corporation shall be such as may be prescribed by rules. Further, the amending legislation provides that the provisions made under the proposed Bill shall not include persons engaged or appointed on daily wages, casual, ad hoc or work charged basis.

5. Since the provisions made under the Bill relate to the service conditions of the employees working in Prasar Bharati,

***The Committee invited views of various Staff Employees Associations and also heard the views of the representatives of two Associations viz. National Federation of Akashvani and Doordarshan Employees (NFADE) and Akashvani and Doordarshan Administrative Staff Association (ADASA)*.**

The representatives of the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati briefed the Committee about the provisions made in the Bill at their sitting held on 20 October, 2010. The Committee took oral evidence of the representatives of the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati at their sitting held on 23 November, 2010. The representatives of the Legislative Department and Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice assisted the Committee in clarifying the various legal issues involved. The Committee in the process of examination of the Bill called for written replies to various issues that emerged during the deliberations on the provisions made under Bill from the Ministry of Information and Broadcasting as well as Prasar Bharati. Having examined the provisions made under the Bill after due deliberations and in consultation with the representatives of the Staff/Employees Associations, the Committee could arrive at their views on the various provisions made in the Bill. The detailed position with regard to the deliberations alongwith the recommendations/observations of the Committee with regard to the provisions made in the Bill has been given in the subsequent Chapters of the Report.

उनके अनुयायी कहा रहे हैं की वे पुनः NFADE के प्लेटफॉर्म से आंदोलन करेंगे और PB एम्प्लॉइज को Govt. Status दिलवायेंगे लेकिन NFADE है कहाँ ? NFADE में ARTEE, ADEA, PSA, ADASA, ADSA, AAA नहीं है और अब ADTEA ने भी पल्ला झाड़ लिया है । NFADE पूर्णतया अप्रासंगिक हो चुका है । हाल ही में उन्होंने फर्जी NFADE प्लेटफॉर्म से अपनी chargesheet withdraw करवाने के लिए आंदोलन किया था । क्या हुआ ? क्या चार्जशीट withdraw हुई ?

PB employee भाइयों वास्तविकता को पहचानिये । यदि ये कटऑफ डेट्स 25/2/1999 और 05/10/2007 नहीं होती तो आप आज हायर स्केल में Govt एम्प्लॉइज होते । आप की आज की अनिश्चित अवस्था के लिए same people पूर्णतया जिमेदार है । आज उनको ARTEE छोड़ने के बाद खड़े होने के लिए आपका साथ चाहिए तो अपने आपको आपका मसीहा दिखने की कोशिश कर रहे हैं । जब उनके हाथ में पूरी ताकत थी तब दो दो cutoff dates का उपहार दिया अब जब खुद ही chargesheet लिए बैठे हैं तो आप लोगो को क्या बचाएंगे ?

PB EMPLOYEES OPEN YOUR EYES